अराज में मीडिया भी शामिल है

कहाँ तो तय था चिरागों हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, हम बहुत कठिन समय में पहुंच चुके हैं। ऐसा कहना इसलिए ठीक है कि जब मूल्यहीनता सबसे नीचे की सीढ़ी या सबसे पहली पीढ़ी तक आ जाती हैं तब उसे बदल पाना सहज नहीं होता। पत्रकारों की पहली सीढ़ी या पीढ़ी जिले और तहसील के पत्रकार हैं। दिल्ली के पत्रकार एवं प्रबंधक वर्ग को संभवत: यह पता नहीं होगा कि जिस मूल्य-धारा को उन्होंने समय सापेक्ष मानकर अपने काम और जीवन में स्वीकार कर लिया है, वह नीचे तक पहुंचकर पत्रकारिता की पूरी मूल्यधारा को परिवर्तित कर चुकी है। पत्रकार और प्रबंधकों के सहारे मीडिया के प्रकाशन और प्रसारण में बाजार और समाज की वह मूल्य धारा अंगजा हो चुकी है, जिसे मूल्यधारित मानवीय समाज रचना का सहायक तो कतई माना नहीं जा सकता है।

'पद्मावत' ही नहीं, उससे पहले के बहुतेरे आंदोलन, चाहे वे शिक्षा क्षेत्र के हों या अन्य क्षेत्रों के, उनके बारे में सच यह है कि वे राजनीतिक या निहित स्वार्थ के लिए उन लोगों ने विकसित और पल्लवित किये जो उससे होने वाली क्षति का आंनद लेने से जरा भी नहीं हिचके या शर्माये। इन लोगों के वास्तविक चेहरे भी लोगों के सामने कभी नहीं आये क्योंकि मुखोटे दूसरे ही लोगों के थे। इन सत्तर बरसों में कितना नुकसान हुआ है और कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, इसका आंकलन न सरकार के पास है और न उन लोगों के पास है जो इस बर्बादी के आधार रहे हैं। मीडिया ने भी कभी इसे न तो पूरी तरह से समझा और न तटस्थ होकर इस पर अपना अनुसंधान किया। संभवत: इसलिए भी कि उन लोगों ने ही मीडिया को या तो भ्रम में रखा या फिर मीडिया को अपने सहयोग के लिए राजी कर लिया। पूरा तंत्र और हमारे अगुआ लगातार झूठ बोलते रहे और पूरे देश के लोगों को आपसी रंजिश और नफरत की आग में झोंकते रहे हैं। याद करें, कि इतने बरसों तक हम किससे लड़ते और नफरत करते रहे हैं और क्या इस सबका परिणाम हमारे बीच पैदा हो चुकी खाईयों के रूप में मौजूद नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब नई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया जिसमें आम लोग ही सत्ता के संगठक और उसके संचालक होते हैं। उस समय लोग लोकतंत्र जैसी नई राजनीतिक व्यवस्था के संबधं में न तो जानकार थे और न ही शिक्षित। पर व्यवस्था लागू हो गई, चुनाव होते गये, नेता सत्ता पर काबिज होते गये। इस सबके दौरान लोग बिना समझ के ही लोकतंत्र को चुनाव के रूप में ही चलाते रहे हैं। किसी ने भी लोकतंत्र संबंध में लोगों को शिक्षित-प्रशिक्षित नहीं किया। सूचना और विचार के मीडिया तंत्र ने भी लोगों को इस बारे में शिक्षित नहीं किया। यह कहा जा सकता है कि मीडिया की ऐसी कोई प्राथमिक या आवश्यक जिम्मेदारी नहीं है कि वह लोगों को लोकतंत्र को शिक्षा दे। पर जब वह शासन के समाचार देता है, लोगों को भागीदारी के लिए प्रेरित करता है,

सत्ता के मूल्यांकन के लिए लोगों से कहता है या सत्ता के पुन: गठन के लिए मतदान करने के रूप में उनका आह्वान करता है, तब वह उसकी जवबादारी तो होती है कि उसके कथन को यानी उसके अर्थ को लोग समझ लें और समझकर अपनी भूमिका तय करें। मीडिया की सूचना-भाषा एक तरह से तकनीकी या अकादमिक भाषा के रूप में होती है जिसके निहितार्थ को वे लोगों ही समझ पाते है जो उस विषय में शिक्षित हैं। इस मायने में उसे लोगों को इस बाबत शिक्षित करना था पर उसमें यह नहीं किया। फलत: एक जगंल राज कायम होता चला गया है जिसमें खिलाड़ियों को तो पता है कि खेल के नियम क्या हैं, पर देखने वालों को यह सब कुछ पता नहीं है और उन्हीं को निर्णायक बना दिया गया है। इसीलिए कई बार 'चलते-चलते लोग चिल्लाने लगे हैं' जैसी स्थितियां पैदा होती रही हैं। मज़ा यह है कि सारे खिलाड़ी और सत्ता भोगी तथा मीडिया के लोग इन निर्णायक लोगों को नासमझ कहते हुए सारी अव्यवस्था के लिए उन्हें ही दोषी ठहराने में देर नहीं करते। यदि मीडिया लोकशिक्षक है तो उसे अपनी इस जिम्मेदारी को भी तो समझना चाहिये। मीडिया आजादी के बाद से आज तक लोगों के लिए जानकारियां और विचार देने का मंच बना हुआ है। अभी भी यह आदर्श स्थिति मानी जाती है कि वह अपनी ओर से केवल सम्मादकीय स्तंभ में ही विचार व्यक्त करता है। बाकी सारी सामग्री लोगों की ही होती है जिसे वह लगभग ज्यों की त्यों प्रस्तुत करता रहा है। यह सभी लोग जानते हैं कि सत्ता के लोग अपनी हर बात और कदम को विकास बताते हैं और विरोध करने वाले उसके ही कदम और विचार का विरोध करता आ रहा है। ज्यादातर लोग भी इस या उस तरफ ही खड़े होते रहे हैं, बाजार के लोग अपने हितों के लिए इसके या उसके साथ होते हैं। ऐसे में बहुत कम या कहें नगण्य संख्या उनकी है जो अपनी अलग राय रखते हैं। उनके पास अपनी बात कहने का माध्यम भी नहीं होता है। इन सत्तर वर्षों में तो यही होता रहा है। ऐसे में यह उचित ही होगा कि माध्यम जो इन सब विचारों को मंच की तरह प्रस्तुत करता रहा है, उसे उन सब जानकारियों और विचारों का लोक हित में विवेचन, विश्लेषण तथा व्याख्या करनी चाहिये जिससे लोग प्रस्तुत संवादों को समझ सकें तथा अपनी राय बना सकें। ऐसा न होने पर माध्यम भी अराज, अव्यवस्था तथा अहितकारी नीतियों का दोषी ठहराया जायेगा और उसे ठहराया जाना भी चाहिए।

ooo